





  
 राजस्थान सरकार  
 Government of Rajasthan

अर्थात् वर्ग की जाकर निम्नानुसार कार्यावाही आरम्भ की गयी  
 और निम्नलिखित विधिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण  
 की बैठक अधीन के जूनियर बार पर सुनी गयी। अधीनस्थ के विद्वा  
 अधिवक्ता ने मामले के तथ्यों एवं अधीनस्थों में वर्तित विर्तुओं को  
 दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र  
 दिनांक 17 नवम्बर 2017 को पेश हुआ, 02 फरवरी 2018 को अधीनस्थ  
 सरखा एक की ओर से अकालतनामा पेश हुआ, अधीनस्थ सरखा 10, 7,  
 5, 2 की समुचित एवं सम्यक तामील नहीं हुई। 18 मई 2018 तक मौके  
 की रिपोर्ट भी अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त नहीं हुई, 21 मई 2018 को  
 प्रकरण केम्य कोर्ट साईं में पेश हुआ, उस दिन आदेशिका में मौका  
 रिपोर्ट प्राप्त हुई मगर बकाया अपीलानों की सम्यक तामील के बिना  
 ही मामले में आगामी पेशी दिनांक 29 मई 2018 को अधीनस्थ आदेश  
 पारित कर दिया गया, जो कि सी भी दंड से न्यायोचित एवं  
 परिष्कारात् है। अधीनस्थ के विद्वा अधिवक्ता ने यह भी  
 नाहित किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने मौका  
 रिपोर्ट कमेश: दिनांक 18 मई 2018 एवं 25 मई 2018 उभय पक्षकारान  
 की उपस्थिति में नहीं बनी गयी है। अतः अधीन अधीनस्थ  
 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ आदेश निरस्त करमाया जावे तथा  
 प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निरिधत पक्षकारान की सुनवाई कर  
 न्यायोचित निर्णय पारित करने हेतु रिमाउड किया जावे।



अधीनस्थ द्वारा आगोचर अधीनस्थ पेश की गयी है।  
 अधीनस्थ के तथ्यों पर उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया। जिसके विरुद्ध  
 अन्तः दिनांक 29 मई 2018 को प्रकरण न्याय आणके द्वारा केम्य कोर्ट  
 मध्य परस्पर समझौदा से मामला सुलझाने के प्रयास भी किये गये,  
 रिपोर्ट तलब की। मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के



